विषय : निवास स्थान पर सरकारी टैलीफोन के अभाव के कारण प्राईवेट टैलीफोन को सरकारी टैलीफोन में बदलना ।

———— ——

क्या सभी वित्तायुक्त एवं प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार उपरोक्त विषय की ओर ध्यान देने का कष्ट करेंगे ?

2. कुछ विभागों से ऐसे प्रस्ताव प्राप्त होते रहते हैं कि उनके अधिकारियों के निवास स्थान पर लगे प्राईवेट टैलीफोन से सरकारी टैलीफोन घोषित कर दिया जाए क्योंकि दूरसंचार विभाग को टैलीफोन लगाने में देरी लग रही है और सरकारी कार्य में बाधा पड़ रही है । मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि इस विभाग की हिदायतों के अनुसार जो अधिकारी निवास स्थान पर टैलीफोन की सुविधा के पात्र हैं लेकिन किसी कारणवश सरकारी टैलीफोन उपलब्ध होने में देरी हो रही है, तो जब तक सरकारी टैलीफोन उपलब्ध न हो तब तक सम्बन्धित अधिकारी के निजी/प्राईवेट टैलीफोन को सरकारी टैलीफोन घोषित करने की कार्यवाही करने के लिए प्रशासकीय सचिव को क्षमता होगी ।

उप-सचिव (पी० एण्ड एस०)
कृते : आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग ।

सेवा में

सभी वित्तायुक्त एवं प्रशासकीय सचिव,
हरियाणा ।

क्रमांक 14/2/93-3 पी०एस० दिनांक 5-3-93